## राग दरबारी



### बहस बहुत जरूरी है

लोकतंत्र में बहस बहुत जरूरी है। बहस कहीं भी, कभी भी की जा सकती है। बहस का का क्या, मतलब की हो या बेमतलब की, पर की जा सकती है। बहस जरूरत की हो सकती है, गैर जरूरी भी की जा सकती है। बहस का क्या.., श्लीलता से भी की जा सकती है, उसमें अश्लीलता भी शामिल की जा सकती है। बहस सादगी संपन्नता से भी हो सकती है, विचार विपत्र उच्छृंखलता भरी भी हो सकती है। ◦सैलेक्टीव◦ हो या ◦इलेक्टिव◦ कुछ भी हो चुनौती देकर बहस का मजा ही अलग है पर जैसे भी हो बहस का होना बहुत जरूरी है...!

प्रायः बहस बाअदब नायाब तरीके से ही होनी चाहिए पर कभी कभी बेअदबी भरी भी हो जाती है। बहस तर्क से सुघड़ होती है वहीं कुतर्क से वाद-विवाद को पनाह मिलती है। बहस बेढंगी, बेदर्द भी होती है। बिना चुनौती सहजता से अनुमोदित बहस की जा सकती है वहीं बहस के लिए चुनौतियों का सोपान भी चढ सकते हैं। जो भी हो बहस मगर जरूरी है...!

किसी लक्ष्य के सापेक्ष बहस हो सकती है, तो कभी निर्विकार निरपेक्ष बहस भी आयामित रह जाती है जग बहस से अपेक्षा अधिक रखते हैं जबकि मूल मुद्दे उपेक्षित रह जाते हैं। अपेक्षाओं की उपेक्षा हो तो बहस निरर्थक रह जाती है।

सार्थकता का अंश न रहे तो बहस करना बेकार है। बहस में संवेदना स्पंदित होती है मगर वहीं आंकड़ों के आघात से विघटन कारी, संकट भरी रह जाती है।बहस से संकट की घड़ियाँ जागृत होती है तो हो पर बहस बहुत जरूरी है...!

बहस का क्या..., घर-परिवार में भी हो सकती है,सामाजिक स्तर हो या कीटी क्लब, बहस कहीं भी हो सकती है। शिक्षण संस्थान हो या व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बिना किसी ◦इफ-बट◦ के बहस करी जा सकती है। स्तर हो या स्तरहीन किसी भी स्तर, राज्य स्तरीय हो , राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, किसी भी स्तर पर बहस हो सकती है। बहस लाजमी है और होती भी है तो कभी कभी बहस में सात्विकता दब कर रह जाती है और भ्रष्टता के पुष्प निखर बहस को अप्रमाणिकता के अंकुश में लपेटती है। बहस से सुमन सौरभ बिखरे या ना बिखरे पर हर हाल में बहस बहुत जरूरी है...!

वाद-विवाद से इतर किसी भी वाद पर बहस हो सकती है चाहे पूंजीवाद हो, साम्यवाद हो, समाजवाद हो या राष्ट्र वाद हो। कैसा भी वाद हो, चाहे भाव विवाद हो, बहस तो बहस है हर हाल में होना जरूरी है...!

भाव उद्वेलित हो, चाहे लज्जा प्रताड़ित हो, संकट की घड़ी हो चाहे परिस्थितियां विकट खड़ी हो, स्नेह अनुकंपित हो चाहे मन प्रकंपित हो, मन निरीह शीतलता ओढे हो चाहे उष्ण संवेग संपादित हो, मन में तूफानी झंझावात हो चाहे मृदुल कोमल भाव प्रदीप्त हो, खुशी से मन तरंगित हो चाहे घर्षण, विकर्षण से अनुमोदित हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, कोई दूर हो या निकट हो, हर बंदे से, हर स्थित में बहस की जा सकती है। दिन हो या रात हो, फोन हो या रूबरू हो बहस कहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो बहस बहुत जरूरी है...!

अलओपी ने पीएम को खुली चुनौती दी, किसी टीवी चैनल पर या कही और,, कभी भी, किसी भी समय बहस करे पर पीएम ने कोई तवज्जो ही नहीं दी जबकि बहादुरों में चुनौतियों को स्वीकार किया जा सकता है। बल्कि गृहमंत्री ने प्रत्युत्तर दिया कि आओ सदन में चुनौती स्वीकार है वहाँ बहस करो।

सदन की बजाय सड़क पर बहस चाहते हैं क्योंकि सदन में सच बोलना पड़ता है। सत्य प्रतिपादन के लिए प्रमाण जरूरी है वो शायद उनके पास नहीं है। सदन के बाहर कुछ जरूरी नही है बस बोलना है। सड़क पर बहस होगी नहीं, सदन में करना नहीं चाहते, ना नौ मन तेल होना, ना राधा नाचनी,ना मैं बहस करना चाहता, जो करना चाहे करे पर बहस बहुत जरूरी है...!

अवसाद में हो, विषाद में हो, खुश हो ना हो, बहस करी जा सकती है। आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, फिर नेता तो डबल आजाद, कौन रोके, कौन टोके। सबके अपने निजी विचार, व्यक्तिगत स्वार्थ पर मुश्किल सह पाना आघात। स्वार्थ संपादन में निष्पक्षता बेमौत मरती हो। विचार संकुचित हो या विकसित हो, मीडिया ट्रायल में खो जाते हैं अपनत्व के भाव। मगर कुछ भी हो, हर हाल में बहस बहुत जरूरी है....!

छत्र छाजेड़ फक्कड़
बी -76 आनंद विहार दिल्ली - 110092 मो. - 9350051179

# वोट चोरी के आरोपों की लड़ाई में बूथ पर ही कमजोर कांग्रेस

इंदौर। वोट चोरी के आरोपों को लेकर देशभर में चुनावी पारदर्शिता का सवाल उठा रही कांग्रेस के सामने मध्य प्रदेश में अपनी ही चुनावी तैयारी की चुनौती खड़ी है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की शुरुआत 12 नवंबर से होने जा रही है, लेकिन पार्टी अभी सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) तक तैनात नहीं कर पाई है।

प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 32 पर नियुक्ति की प्रक्रिया अधूरी है। ऐसे में मतदाता सूची में गड़बड़ी रोकने और नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने की लड़ाई में कांग्रेस को बूथ स्तर पर अपनी मौजूदगी मजबूत करनी होगी।

प्रदेश में कुल 71,930 मतदान केंद्र हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के साथ राजनीतिक दलों के बीएलए की भूमिका भी अहम रहेगी। बीएलए मतदाता सूची की जांच, छूटे हुए नामों की पहचान, अपात्र नामों पर आपत्ति और संशोधन की प्रक्रिया में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में हर बूथ पर सक्रिय एजेंट नहीं होना कांग्रेस के लिए संगठनात्मक कमजोरी के साथ चुनावी चुनौती भी है।

### आरोप राष्ट्रीय स्तर पर, तैयारी बूथ स्तर पर अधूरी

कांग्रेस लगातार चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठा रही है। पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में एसएसआर शुरू होने से पहले पार्टी का पूरा बूथ नेटवर्क तैयार नहीं है।

डिंडौरी और आलीराजपुर सहित 32 विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए नियुक्त नहीं हो सके हैं। यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में छोटी-सी चूक भी चुनाव के समय बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम छूटता है या किसी अपात्र नाम को लेकर आपत्ति दर्ज नहीं हो पाती, तो पार्टी के पास बूथ स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप का मजबूत तंत्र होना जरूरी है।



### संगठन सृजन के बाद भी नहीं बन पाया पूरा नेटवर्क

कांग्रेस ने पिछले दो वर्षों में संगठन सृजन अभियान के जरिए बूथ स्तर तक अपनी टीम खड़ी करने पर जोर दिया है। पहली बार बीएलए की नियुक्तियों का रिकॉर्ड तैयार कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर नाम और मोबाइल नंबर अपलोड कराए गए। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान इन एजेंटों को सक्रिय भी किया गया। हालांकि, इस प्रक्रिया में कई जगह नियुक्त बीएलए के निष्क्रिय होने की शिकायतें सामने आईं। इसके बाद पार्टी ने ऐसे एजेंटों को बदलने की कवायद शुरू की। अब नए सिरे से सत्यापन कराया जा रहा है, ताकि कागजों में दर्ज नामों के बजाय वास्तव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा सके।

### कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती

एसएसआर के दौरान कांग्रेस को दो मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने और गलतियों को दुरुस्त कराने का। दूसरा, हर बूथ पर ऐसा कार्यकर्ता तैनात करना जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रख सके।

**- 32 सीटों पर संगठन का पहरा अधूरा,198 विधानसभा क्षेत्रों में ही बीएलए की सूची अपलोड**

इसके लिए केवल नियुक्तियां पूरी करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि एजेंटों को प्रशिक्षित और सक्रिय रखना भी जरूरी होगा। भाजपा के संगठनात्मक नेटवर्क को देखते हुए कांग्रेस के लिए यह चुनौती और बड़ी हो जाती है।

प्रदेश में 71,930 बूथों पर राजनीतिक मुकाबले की तैयारी के बीच पार्टी को अपने एजेंटों की उपलब्धता और सक्रियता दोनों सुनिश्चित करनी होंगी।

### एसएसआर से पहले नियुक्तियां पूरी करने का दावा

प्रदेश कांग्रेस में मतदाता सूची संबंधी कार्य के प्रभारी ललित सेन का कहना है कि 198 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त बीएलए की सूची वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है।

शेष विधानसभा क्षेत्रों में एसएसआर शुरू होने से पहले नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। संगठन महासचिव संजय मालवे के मुताबिक, प्रत्येक बीएलए का सत्यापन कराया जा रहा है। विधानसभा प्रभारियों से एजेंटों के नाम, मोबाइल नंबर और काम करने की इच्छा को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। जो कार्यकर्ता जिम्मेदारी निभाने के इच्छुक नहीं हैं, उनके स्थान पर दूसरे लोगों को नियुक्त किया जाएगा। वहीं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने सभी राजनीतिक दलों से बीएलए नियुक्त करने का आग्रह किया है।

अब कांग्रेस के सामने असली परीक्षा नियुक्तियों की सूची पूरी करने से आगे की है। वोट चोरी के आरोपों पर राजनीतिक लड़ाई तभी बूथ तक प्रभावी होगी, जब पार्टी के पास हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता और मतदाता सूची की निगरानी का मजबूत तंत्र होगा।

# गरीब हितग्राहियों के नाम पर रसूखदारों के घर बंधी मिलीं भैंसें!

## मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप

इंदौर। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में इंदौर जिले के चारों विकासखंडों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं एवं कथित भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। भारतीय किसान एवं मजदूर सेना (अ) के अध्यक्ष बबलू जाधव ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों तथा हितग्राहियों के घर-घर जाकर किए गए स्थलीय सत्यापन के आधार पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपसंचालक को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जाँच एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।

बबलू जाधव ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब हितग्राहियों के नाम पर योजना का लाभ स्वीकृत किया गया, लेकिन कई मामलों में भैंसें वास्तविक हितग्राहियों के घरों पर मिलने के बजाय अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के घरों पर बंधी होने की जानकारी सामने आई है। कई हितग्राहियों के घर पर भैंसें नहीं मिलीं। वहीं योजना के अभिलेखों में दर्ज मोबाइल नंबरों में भी कथित हेरफेर की शिकायत सामने आई है।

उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में एक ही परिवार के दो-दो व्यक्तियों को योजना का लाभ दिए जाने की जानकारी मिली है। पशुओं की वास्तविक खरीद, भुगतान, बीमा, टैगिंग, परिवहन एवं हितग्राहियों को पशु सुपुर्द किए जाने से संबंधित दस्तावेजों की भी गहन जाँच आवश्यक है।

एक माह बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं, विभाग की चुप्पी पर सवाल!

बबलू जाधव ने कहा कि इन गंभीर अनियमितताओं को लेकर उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग, इंदौर को लिखित शिकायत सौंपे हुए एक माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक न तो कोई ठोस कार्रवाई सामने आई है और न ही जाँच की प्रगति की जानकारी दी गई है। विभाग की इस चुप्पी से यह गंभीर आशंका उत्पन्न हो रही है कि कहीं न कहीं मामले को दबाने और जिम्मेदार लोगों को संरक्षण देने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। आखिर गरीब एवं वंचित वर्ग के हितग्राहियों के अधिकारों से जुड़े इतने गंभीर मामले में विभाग कार्रवाई करने से पीछे क्यों हट रहा है?



बबलू जाधव ने सवाल उठाया कि गरीब हितग्राहियों के नाम पर स्वीकृत सरकारी सहायता आखिर किन लोगों तक पहुँच रही है? यदि योजना का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्ति के बजाय अन्य व्यक्तियों को मिला है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय होना आवश्यक है।

संगठन की प्रमुख मांग है कि इंदौर जिले के चारों विकासखंडों में लाभान्वित सभी हितग्राहियों का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन कराया जाए। मूल आवेदन, मोबाइल नंबर, बैंक भुगतान, पशु खरीद, बीमा एवं टैगिंग रिकॉर्ड का मिलान किया जाए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के नाम पर दूसरों को लाभ पहुँचाने के मामलों की प्राथमिकता से जाँच हो तथा एक ही परिवार में एक से अधिक व्यक्तियों को दिए गए लाभ की पात्रता भी संबंधित नियमों के अनुसार जाँची जाए।

बबलू जाधव ने कहा कि जाँच में यदि अधिकारी, कर्मचारी, बिचौलिए या अन्य व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध कठोर विभागीय एवं वैधानिक कार्रवाई की जाए तथा अनुचित तरीके से प्राप्त शासकीय राशि की वसूली भी की जाए। वास्तविक पात्र हितग्राहियों को योजना के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाए।

### उच्चस्तरीय जाँच नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

इस मामले में शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव, संभागायुक्त इंदौर एवं कलेक्टर इंदौर को भी भेजी गई है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि एक माह बीतने के बावजूद विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं करना गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि अब भी निष्पक्ष एवं समयबद्ध जाँच शुरू नहीं की गई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो भारतीय किसान एवं मजदूर सेना वरिष्ठ अधिकारियों एवं संबंधित जाँच एजेंसियों के समक्ष मामला उठाने के साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। गरीब हितग्राहियों के अधिकारों और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

# प्रभारी मंत्री के बदलते ही बनेंगे नए समीकरण

इंदौर नगर प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर का प्रभारी मंत्री का पद छोड़ दिया है और उनकी जगह पर मंत्री चैतन्य काश्यप को इसकी जिम्मेदारी दी गई है इंदौर की सियासत में एक और गुट तैयार हो गया हैं। उल्लेखनीय की एक समय था जब इंदौर की भाजपा की सियासत में सबसे पहला नाम राजेंद्र धरकर का हुआ करता था उसके बाद निर्भय सिंह पटेल और कृष्ण मुरारी मोघे दौर भी आया।

सुमित्रा महाजन और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय के गुट की शुरुआत हुई साथ ही सांसद शंकर लालवानी का गुट भी शुरू हो गया। ताई भाई और साइ के नाम से इंदौर की सियासत गर्म होने लगी साथ ही नए-नए अच्छा सामने आने लगे।

मुख्यमंत्री के पद पर मोहन यादव की नियुक्ति होने के बाद इंदौर में उनका जलवा शुरू हो गया था गृहमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री भी वही थे और इसी के कारण राजनीतिक जमत बढ़ती जा रही थी परंतु मुख्यमंत्री ने इंदौर का प्रभार छोड़ दिया और चैतन्य काश्यप को इसकी जिम्मेदारी दे दी।

कश्यप के पास भोपाल के अलावा एक और जिला शामिल था और अब इंदौर जैसे शहर की जिम्मेदारी भी उनके हिस्से में आ गई। चैतन्य काश्यप की इंदौर में राजनीति शुरू होने के साथी सियासत के एक और नेट का आगाज हो गया है।

कश्यप में जितनी राजनीतिक समझ है उसके बाद इंदौर में मंत्री गुट को संभालना आसान नहीहैं। यहां पर पहले से ही दो मंत्री तैनात है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट शामिल है। इनका साथ में लेकर चलना बड़ा मुश्किल काम है और नियुक्तियां या तबादले में सहयोग करना। कुल मिला कर इंदौर की सियासत निर्णायक मोड़ पर पहुंच गईहै।

# मध्यप्रदेश में नए डीजीपी पर आखिरी वक्त तक सस्पेंस

इंदौर। मध्यप्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर असमंजस बरकरार है। मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाणा का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब तक न तो उनके कार्यकाल में विस्तार का आदेश जारी हुआ है और न ही नए डीजीपी के नाम पर सरकार ने मुहर लगाई है। महज तीन दिन शेष रहने के कारण पुलिस मुख्यालय से लेकर आईपीएस अधिकारियों के बीच हलचल तेज हो गई है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार मौजूदा डीजीपी मकवाणा को एक्सटेंशन देकर फिलहाल स्थिति यथावत रखेगी या फिर यूपीएससी की प्रक्रिया के तहत भेजे गए तीन अधिकारियों के पैनल में से किसी एक को प्रदेश की कमान सौंपेगी। सरकार के फैसले को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया के तहत यूपीएससी के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव और डीजीपी की बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया था। इसके बाद वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम का पैनल सरकार को भेजा गया। पैनल में उपेंद्र जैन का नाम सबसे आगे बताया जा रहा था, जबकि प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव दूसरे क्रम पर बताई जा रही हैं।

यदि सरकार उनके नाम पर सहमति जताती है तो मध्यप्रदेश को पहली महिला डीजीपी मिल सकती हैं। वहीं वरुण कपूर भी इस दौड़ में शामिल हैं। डीजी ईओडब्ल्यू उपेंद्र जैन की दावेदारी के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से उनकी रिश्तेदारी को लेकर भी चर्चा है। हालांकि, इस रिश्ते का चयन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे लेकर कोई आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है।

### एक्सटेंशन के प्रस्ताव ने बदला समीकरण

नियुक्ति प्रक्रिया के बीच 20 नवंबर को राज्य सरकार की ओर से डीजीपी कैलाश मकवाणा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजे जाने की चर्चा सामने आई। इससे नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर चल रही अटकलों को और बल मिला है। यदि मकवाणा को एक्सटेंशन मिलता है तो फिलहाल नए डीजीपी की नियुक्ति टल सकती है।

वहीं, सरकार पैनल में शामिल किसी अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपती है तो एक दिसंबर से प्रदेश पुलिस की कमान नए अधिकारी के हाथ में होगी। पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल मकवाणा के एक्सटेंशन का कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। आदेश जारी होने पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

**30 नवंबर को खत्म हो रहा कैलाश मकवाणा का कार्यकाल, सिर्फ तीन दिन शेष**
**- वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम पैनल में, सरकार के फैसले का इंतजार**

### विदाई परेड की तैयारी भी बनी चर्चा का विषय

डीजीपी के कार्यकाल को लेकर असमंजस का असर पुलिस मुख्यालय की गतिविधियों में भी दिखाई दे रहा है। चर्चा है कि 24 नवंबर को डीजीपी की विदाई परेड के लिए प्रदेशभर से बुलाए गए पुलिसकर्मियों को वापस भेज दिया गया। इससे यह संकेत मिला कि विदाई कार्यक्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

दूसरी ओर, डीजीपी के ओएसडी का तबादला होने के बावजूद उन्हें अभी रिलीव नहीं किया गया है। इन घटनाक्रमों को भी मकवाणा के संभावित एक्सटेंशन से जोड़कर देखा जा रहा है।

### 30 नवंबर को आखिरी दिन, छुट्टियों के बीच फैसला

कैलाश मकवाणा का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद एक दिसंबर से नए डीजीपी की नियुक्ति या मौजूदा डीजीपी के विस्तारित कार्यकाल की स्थिति स्पष्ट होनी है। खास बात यह है कि 28 और 29 नवंबर को सरकारी अवकाश है। ऐसे में प्रशासनिक और पुलिस महकमे की नजर सोमवार 30 नवंबर पर टिकी है। सरकार के सामने अब दो विकल्प हैं–मकवाणा को एक्सटेंशन देकर फिलहाल बदलाव टालना या तीन नामों के पैनल में से किसी एक अधिकारी को प्रदेश पुलिस की कमान सौंपना। आखिरी फैसला किसके पक्ष में होगा, इसका इंतजार अब महज तीन दिन का रह गया है।

### कार्टून कोना




नदी पार करते समय कंधे से फिसले RJD विधायक, धड़ाम से पानी में गिरे